गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 222
दि. 13.12.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

डिजिटल दौर में देश की सबसे बड़ी गिनती, 2027 की जनगणना पर 11,718 करोड़ का निवेश, हर नागरिक पर औसतन 97 रुपये का खर्च

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत सरकार ने वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इसके लिए 11,718 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई, जिसके साथ ही देश की 16वीं और आजादी के बाद आठवीं जनगणना की औपचारिक तैयारी शुरू हो गई है। यह जनगणना कई मायनों में खास होगी, क्योंकि पहली बार इसे पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराया जाएगा और इसमें जाति आधारित आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में प्रति व्यक्ति औसतन करीब 97 रुपये का खर्च आएगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायदों में से एक मानी जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2027 की जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में घरों की सूचीकरण और आवासीय जनगणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच संपन्न कराई जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में देश की वास्तविक जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में की जाएगी। हालांकि, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे बर्फबारी वाले क्षेत्रों में मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए यह गणना सितंबर 2026 में ही कर ली जाएगी। जनगणना की संदर्भ तिथि देश के अधिकांश हिस्सों के लिए एक मार्च 2027 की आधी रात तय की गई है, जबकि बर्फीले इलाकों के लिए यह एक अक्तूबर 2026 होगी। इस बार की जनगणना को तकनीक के लिहाज से एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सरकार ने इसे भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक विशेष मोबाइल एप तैयार किया गया है, जो हिंदी, अंग्रेजी के साथ सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। इसी के जरिए गणनाकार घर-घर जाकर जानकारी दर्ज करेंगे। इसके अलावा एक केंद्रीय पोर्टल सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जिसके माध्यम से पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। हर घर और हर क्षेत्र की जियो-टैगिंग की जाएगी, ताकि आंकड़ों की सटीकता पर कोई सवाल न उठे और किसी तरह की दोहराव या चूक की गुंजाइश न रहे। इस जनगणना की सबसे अहम और चर्चित विशेषता जाति आधारित आंकड़ों को शामिल किया जाना है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इसे मंजूरी दी है, जिससे पहली बार जाति गणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी। सरकार का मानना है कि भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में जाति से जुड़ा सटीक डेटा सामाजिक न्याय,

कल्याणकारी योजनाओं और नीति निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाओं को सही वर्ग तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ेगी। जनगणना 2027 के लिए करीब 30 लाख कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इनमें गणनाकार, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर और तकनीकी स्टाफ शामिल होंगे। यह पूरी प्रक्रिया लगभग 1.02 करोड़ मानव-दिन का अतिरिक्त रोजगार भी पैदा करेगी। फील्ड में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी सरकारी शिक्षक और अन्य सरकारी कर्मी होंगे, जिन्हें उनके नियमित काम के अलावा यह जिम्मेदारी दी जाएगी और इसके लिए मानदेय भी निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि यह अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल फील्ड ऑपरेशन होगा। गणनाकार टैबलेट या मोबाइल एप के जरिए घर-घर जाकर हर परिवार से जुड़ी विस्तृत जानकारी दर्ज करेंगे। इसमें घर की स्थिति, बुनियादी सुविधाएं, परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा, भाषा, धर्म, रोजगार, विकलांगता, प्रवासन और अन्य सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का डेटा शामिल होगा। डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी तरह की जानकारी लीक न हो और नागरिकों की गोपनीयता बनी रहे। इस बार सरकार ने लोगों को स्वयं-गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प भी देने का फैसला किया है। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा है, वे मोबाइल एप या वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि फील्ड स्टाफ पर दबाव भी कम होगा। जिन इलाकों में डिजिटल पहुंच सीमित है, वहां गणनाकार पहले की तरह घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। सरकार का कहना है कि डिजिटल जनगणना से प्राप्त आंकड़े बेहद तेजी से उपलब्ध होंगे और इन्हें सेंसस-एज-ए-सर्विस के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों को दिया जाएगा। डैशबोर्ड, ग्राफ और मशीन-रीडेबल फॉर्मेट में उपलब्ध यह डेटा नीति निर्धारण और योजनाओं के क्रियान्वयन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। किसी भी क्षेत्र की जरूरतों को समझकर तुरंत फैसले लेने में यह आंकड़े मददगार साबित होंगे।

सरकार ने दोहराया है कि जनगणना किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है। इसके आधार पर ही पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार जैसी योजनाओं की रूपरेखा तय होती है। यही आंकड़े लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण का आधार भी बनते हैं। भारत में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण टाल दी गई थी। अब 2027 की जनगणना से देश को एक बार फिर अद्यतन, व्यापक और भरोसेमंद डेटा मिलने की उम्मीद है, जिस पर आने वाले दशक की नीतियां और योजनाएं टिकी होंगी।

अली तौकीर शेख प्रकरण में खुलासा अधूरा अब केंद्रीय एजेंसियों के हवाले होगी जांच

(जीएनएस)। गुवाहाटी। असम की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में रहे पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को बड़ा बयान देकर संकेत दिया कि राज्य की विशेष जांच टीम इस केस की सभी परतें खोलने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस जटिल और संवेदनशील मामले की आगे की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपी जाएगी, ताकि पूरे नेटवर्क, विदेशी कनेक्शन और संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की गहराई से पड़ताल हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने इस मामले में शुरुआती जांच पूरी कर ली है और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन जांच के दौरान ऐसे कई बिंदु सामने आए हैं, जिनकी तह तक पहुंचने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की तकनीकी क्षमता और अंतरराष्ट्रीय समन्वय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि

जुबिन गर्ग मौत मामले में एसआईटी द्वारा करीब 12 हजार पन्नों की विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई है और जैसे ही उस मामले का नियमित ट्रायल शुरू होगा, वैसे ही अली तौकीर शेख प्रकरण को औपचारिक रूप से केंद्रीय एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरमा ने यह भी संकेत दिया कि इस पूरे मामले से जुड़े कुछ अहम दस्तावेजों को महीने के अंत तक सार्वजनिक किया जा सकता है, ताकि जनता के सामने भी यह स्पष्ट हो सके कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अली तौकीर शेख का मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय संपर्क, संदिग्ध गतिविधियां और राजनीतिक संवेदनशीलता जैसे कई आयाम जुड़े हुए हैं, जिनकी निष्पक्ष और गहन जांच जरूरी है। यह मामला उस वक्त और ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, जब अली तौकीर शेख के कथित संबंध कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी से जोड़े गए। मुख्यमंत्री ने पहले दावा किया था कि एसआईटी की जांच में यह बात सामने आई है कि एक ब्रिटिश नागरिक, जिसने एक भारतीय सांसद से विवाह किया है, उसकी भूमिका अली तौकीर शेख की कथित गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। सरमा ने यह भी कहा था कि जांच में ऐसे संकेत मिले हैं, जिनसे यह समझने में मदद मिलती है कि किस तरह पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्रालय ने असम के एक सांसद की पाकिस्तान यात्रा को सुविधाजनक बनाया। एसआईटी ने विशेष पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) मुन्ना प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में इस मामले की जांच की थी और 10 सितंबर को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसे सार्वजनिक करने से पहले मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा और सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केवल एसआईटी के स्तर पर इस मामले को आगे बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पहले ही इन्हें बेबुनियाद बताया था। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोप किसी सी-ग्रेड बॉलीवुड फिल्म की पटकथा जैसे हैं, जो अंत में फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि असम की जनता सच्चाई समझने में सक्षम है।

न्यायपालिका पर दबाव की साजिश करार, जस्टिस स्वामीनाथन के पक्ष में 56 पूर्व न्यायाधीशों का खुला प्रतिरोध

(जीएनएस)। नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ संसद में पेश किए गए महाभियोग नोटिस को लेकर देश की न्यायिक बिरादरी में गहरी चिंता सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के कुल 56 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने एकजुट होकर इस कदम को न्यायिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर और खतरनाक बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। पूर्व न्यायाधीशों ने सांसदों के नाम एक खुला पत्र जारी कर अपील की है कि इस महाभियोग प्रस्ताव को आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि यह न केवल एक स्वतंत्र न्यायाधीश को डराने का प्रयास है, बल्कि पूरी न्यायपालिका की स्वायत्तता पर सीधा हमला भी है। पूर्व न्यायाधीशों ने अपने बयान में कहा है कि यह महाभियोग नोटिस किसी संवैधानिक या कानूनी कदाचार का परिणाम नहीं, बल्कि उस न्यायिक सोच के खिलाफ प्रतिक्रिया है जो समाज के एक खास वैचारिक और राजनीतिक वर्ग की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने इसे न्यायाधीशों को डराने और उन्हें एक खास

दिशा में फैसले देने के लिए मजबूर करने की कोशिश बताया। पूर्व जजों के अनुसार, यदि ऐसे प्रयासों को स्वीकार कर लिया गया, तो यह लोकतंत्र के उस मूल स्तंभ को कमजोर कर देगा, जिस पर संविधान की पूरी संरचना टिकी हुई है। खुले पत्र में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि महाभियोग जैसी संवैधानिक प्रक्रिया केवल अत्यंत दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही अपनाई जानी चाहिए, जब किसी न्यायाधीश पर गंभीरतम कदाचार के ठोस और निर्विवाद आरोप हों। पूर्व न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नोटिस में बताए गए कारण, चाहे उन्हें पूरी तरह सही भी मान लिया जाए, फिर भी वे महाभियोग जैसी कठोर प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कतई पर्याप्त नहीं हैं। उनका कहना है कि महाभियोग का दुरुपयोग न्यायपालिका को नियंत्रित करने के औजार के रूप में नहीं किया जा सकता। पूर्व न्यायाधीशों ने इस स्थिति की तुलना आपातकाल के दौर से करते हुए चेतावनी दी कि उस समय भी न्यायपालिका पर इसी तरह का राजनीतिक दबाव बनाया गया था और कुछ न्यायाधीशों को सिर्फ कानून का पालन करने के कारण दंडित किया गया था। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि तमाम दबावों के बावजूद भारतीय न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है और आज फिर वैसी ही चुनौती सामने खड़ी की जा रही है।

अपने बयान में पूर्व न्यायाधीशों ने यह भी याद दिलाया कि हाल के वर्षों में यह कोई पहली घटना नहीं है। जब-जब न्यायपालिका के फैसले कुछ राजनीतिक समूहों को रास नहीं आए, तब-तब न्यायाधीशों के खिलाफ हमले, बदनाम करने की कोशिशें और दबाव बनाने के प्रयास किए गए। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के उदाहरण देते हुए कहा कि असहमति को स्वीकार करने के बजाय न्यायपालिका को निशाना बनाना एक खतरनाक परंपरा बनती जा रही है।

पूर्व जजों ने साफ कहा कि यह महाभियोग नोटिस कानूनी आलोचना का हिस्सा नहीं है, बल्कि न्यायाधीशों को नियंत्रित करने और उन्हें एक तयशुदा ढांचे में काम करने के लिए मजबूर करने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आज एक न्यायाधीश को इस तरह निशाना बनाया गया, तो कल पूरी न्यायपालिका को कमजोर करने का रास्ता खुल जाएगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है।

तेलंगाना ग्राम पंचायत चुनाव: कांग्रेस ने पहले चरण में मारी बाजी, बीआरएस और बीजेपी पीछे

(जीएनएस)। हैदराबाद। तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनावों के पहले चरण में सत्तारुढ़ कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है। राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पहले चरण के चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा की, जिससे स्थानीय राजनीति का नक्शा स्पष्ट हुआ। पहले चरण

में कुल कई हजार पदों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने सबसे अधिक सरपंच और उप सरपंच पदों पर कब्जा जमाया। जानकारी के अनुसार, पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस के बाद भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) रहे। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी 455 सरपंच पदों पर जीत हासिल की है, जो स्थानीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता और सामाजिक जुड़ाव को दर्शाता है। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने कुल 3,347 उप सरपंच पदों के परिणामों की भी घोषणा की, जिसमें कांग्रेस का दबदबा स्पष्ट दिखा। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि ग्राम पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण के उत्साही मतदान और परिणामों के बाद दूसरा और तीसरा चरण क्रमशः 14 और 17 दिसंबर को होंगे। इन चरणों में भी राज्य के विभिन्न जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान होगा, जिससे अंतिम रूप से पूरी ग्राम पंचायत संरचना तय होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले चरण में कांग्रेस की मजबूत जीत से आगामी चरणों में भी उसकी स्थिति मजबूती की ओर बढ़ सकती है। दूसरी ओर बीआरएस और भाजपा को अपने आधार को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ बनाने के लिए रणनीति बदलने की आवश्यकता होगी। ग्राम पंचायत चुनावों में स्थानीय मुद्दों, विकास योजनाओं और सामाजिक जुड़ाव का बड़ा असर पड़ता है। इस बार के चुनाव में भी ग्रामीण जनता की प्राथमिकताओं को देखते हुए उम्मीदवारों ने क्षेत्रीय विकास, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को प्रमुख एजेंडा बनाया। चुनाव परिणाम दिखाते हैं कि कांग्रेस ने इन मुद्दों पर जनता का विश्वास जीतने में सफलता पाई।

चुनाव आयोग के अनुसार, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के बाद पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की सीटों का वितरण स्पष्ट होगा। यह परिणाम स्थानीय शासन में सुधार और ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। इस चुनावी प्रक्रिया से ग्रामीण लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और पंचायती राज व्यवस्था में जनता की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

देशभर में 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि में 11,152 एकड़ पर अतिक्रमण, संसद में खुलासा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में सुरक्षा और जमीन प्रबंधन के महत्व को लेकर एक गंभीर तथ्य सामने आया है। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि देशभर में फैली लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि में से करीब 11,152 एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है। यह आंकड़ा न केवल रक्षा संपत्तियों की सुरक्षा को चुनौती देता है, बल्कि प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था की कमजोरी को भी उजागर करता है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लिखित जवाब में बताया कि कुल भूमि में से 8,113 एकड़ जमीन विभिन्न कानूनी विवादों में फंसी हुई है, जबकि 45,906 एकड़ भूमि अतिरिक्त है, जिसे अन्य केंद्रीय विभागों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि रक्षा भूमि का उपयोग केवल सैन्य गतिविधियों, रणनीतिक जरूरतों, प्रशिक्षण, सुरक्षा और सैनिक आवास जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। हालांकि कई जगहें खाली दिखाई देती हैं, वे भविष्य की जरूरतों जैसे ट्रेनिंग, मोबिलाइजेशन ड्रिल, KLP प्लान और मैरिड अकोमोडेशन के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं। इस रिपोर्ट से यह बात भी सामने आई कि अतिक्रमण की स्थिति देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इसे नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने बताया कि अतिरिक्त 45,906 एकड़ भूमि अन्य केंद्रीय मंत्रालयों को आवंटन के लिए दी गई है, ताकि उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग हो सके। वहीं, 8,113 एकड़ भूमि विभिन्न कानूनी विवादों में फंसी हुई है, जिसमें जमीन के मालिकाना हक, पुराने सरकारी दस्तावेज, अधिग्रहण प्रक्रियाओं में खामियां और स्थानीय दावे शामिल हैं। इन विवादित जमीनों को निपटाने के लिए सरकार कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज कर रही है।

संसद में उठाए गए सवाल के जवाब में यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्रामीणों पर भूमि अधिग्रहण और बेदखली के प्रभाव का कोई विशेष आकलन नहीं किया गया है। हालांकि, 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसी भी निजी जमीन के अधिग्रहण पर उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाता है।

रक्षा खरीद बजट के संदर्भ में संसद में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि धीमी खरीद के कारण 12,500 करोड़ रुपये वापस करने की स्थिति नहीं बनी और संशोधित बजट का पूरा उपयोग किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रक्षा खरीद प्रक्रिया को और तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए डीएपी (Defense Acquisition Procedure) में प्रस्तावित संशोधन लागू किए जाएंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़ा और भूमि प्रबंधन से जुड़े विवरण यह स्पष्ट करते हैं कि देश की रक्षा केवल हथियार और सैनिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमि का सही प्रबंधन और उसके अतिक्रमण पर नियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि अतिक्रमण हटाने और अतिरिक्त भूमि के आवंटन से न केवल सेना की तैयारियों में सुधार होगा, बल्कि भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता और कानूनी नियंत्रण भी बढ़ेगा।

इस तरह, संसद में सामने आए आंकड़े और जानकारी देश की सुरक्षा, भूमि प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच एक नाजुक संतुलन की जरूरत को स्पष्ट करते हैं। यह पहल न केवल रक्षा संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अहम है, बल्कि भविष्य में कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की दिशा में भी

संपादकीय

बच्चे बचपन

पश्चिमी देश, जिस सोशल मीडिया के गुणगान करते नहीं अघाते थे, अब उन्हें इससे बच्चों में पनपती विकृतियों की हकीकत समझ में आने लगी है। सुगबुगाहट तो ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक प्रतिबंधों को लेकर हो रही है, लेकिन इस दिशा में पहल करने का साहस आस्ट्रेलिया ने सुधारवादियों के दबाव में उठाया है। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे बड़ी तकनीकी कंपनियों के अधिकार इसलिए वापस ले रहे हैं ताकि बच्चों के बच्चे होने के अधिकार और माता-पिता की मानसिक शांति के अधिकार की रक्षा हो सके। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया है कि यह सुधार जिंदगियां बदल देगा। साथ ही आस्ट्रेलिया के बच्चों को बचपन जीने का मौका देगा। आज दुनिया के तमाम देश मंथन कर रहे हैं यदि आस्ट्रेलिया यह पहल कर सकता है तो वे क्यों नहीं कर सकते। इनमें वे तमाम अभिभावक भी शामिल हैं जो अपने बच्चों की आत्महत्या के लिये सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं। उल्लेखनीय है कि आस्ट्रेलिया में यदि सोशल मीडिया मंच 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट हटाने में असफल रहते हैं, तो उन्हें करीबन पांच करोड़ आस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना चुकाने के लिये बाध्य होना पड़ सकता है। आस्ट्रेलियाई सरकार क्रिसमस तक मूल्यांकन करेगी कि ये प्रतिबंध कितने कारगर साबित हुए हैं। निस्संदेह, आस्ट्रेलिया की पहल ने पूरी दुनिया में सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखने की मुहिम को नई ऊर्जा दे दी है। कमोवेश, भारत जैसे देश भी सोशल मीडिया की असामाजिकता का दंश झेल रहे हैं। इसमें बच्चों के साथ ऑनलाइन बुलिंग से लेकर ऑनलाइन ठगी तक के तमाम मामले गाहे-बगाहे सामने आते रहते हैं। विडंबना है कि आज सोशल मीडिया पर प्रसारित वयस्कों की सामग्री से बच्चे जाने-अनजाने में परिचित हो रहे हैं। वे समय से पहले वयस्क हो रहे हैं। जिससे समाज में तमाम तरह की सामाजिक विकृतियां पैदा हो रही हैं। निस्संदेह, इससे आने वाले समय में घातक सामाजिक विद्रूपताएं पैदा हो सकती हैं।

दरअसल, बच्चों के लगातार घंटों कथित सोशल मीडिया में सक्रिय रहने से उनमें तमाम शारीरिक व मानसिक विसंगतियां पैदा हो रही हैं। उन्हें संस्कार अब माता-पिता व शिक्षक नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का दोहन करने वाले निहित स्वार्थी तत्व दे रहे हैं। जो कि भारतीय जीवन-मूल्यों व संस्कारों से मेल नहीं खाते। आज सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर इतनी अश्लील व द्विअर्थी सामग्री का प्रवाह है कि हमारे किशोर आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। सोशल मीडिया के घातक प्रभाव के चलते आज बच्चों के नायक बदल गए हैं। उनके आदर्श बदल गए हैं। उनका नजरिया बदल रहा है। सोशल मीडिया के कतिपय मंचों पर अश्लील सामग्री की उपलब्धता ने किशोरों में ब्रह्मचर्य के भारतीय मूल्यों को ताक पर रख दिया है। विडंबना यह है कि घंटों सोशल मीडिया पर बैठे रहने वाले बच्चे शारीरिक सक्रियता से दूर हो रहे हैं। जिससे उनमें मोटापा व अनेक गैर संक्रामक रोग पनप रहे हैं। वे किशोर अवस्था में मधुमेह आदि उन रोगों के शिकार बन रहे हैं जो कभी बड़ी उम्र के लोगों को हुआ करते थे। इस संकट का एक घातक पहलू यह भी है कि मोबाइल पर लगातार सोशल मीडिया के कार्यक्रम स्क्रॉल करने वाले बच्चों की मानसिक एकाग्रता बाधित हो रही है। जाहिर है इसका प्रभाव उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर पड़ेगा। एक समय दुनिया के तमाम देशों में जिन भारतीय प्रतिभाओं का डंका बजता था, शायद भविष्य में ऐसा न हो। घंटों सोशल मीडिया पर बिताने वाले छात्रों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे अपनी पढ़ाई के लिये पूरी तरह एकाग्र हो सकेंगे। निरंतर कल्पना लोक में विचरण करने वाले बच्चे जब जीवन की हकीकत से जूझते हैं तो टूटने-बिखरने लगते हैं। गाहे-बगाहे आत्महत्या करने वाले किशोरों के डेटा का यदि गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो निश्चित रूप से हम सोशल मीडिया के घातक प्रभाव की हकीकत से रूबरू हो सकते हैं। आस्ट्रेलियाई पहल से सबक लेकर भारत के नीति-नियंताओं को भी इस दिशा में गंभीरता से पहल करनी चाहिए। इस दिशा में थोड़ी भी देरी की देश को भविष्य में बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

बंगाल में उभरते हिन्दू स्वरों में बदलते राजनीतिक समीकरण

> निश्चित ही बाबरी मस्जिद विवाद को हवा देकर कुछ मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक वर्गों ने तनाव का वातावरण खड़ा किया है। इन दो समानांतर धाराओं की टकराहट ने बंगाल को विमर्श के केंद्र में ला दिया है कि क्या राज्य में हिंदू संगठित होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हिन्दू-विरोधी साजिशों एवं षडयंत्रों का अंत चाहते हैं?

पश्चिम बंगाल इन दिनों धार्मिक और राजनीतिक उफान का केंद्र बना हुआ है। बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक समूहों की सक्रियता के बीच हिन्दू धर्मगुरुओं एवं संगठनों की मोर्चाबंदी ने क्या हिंदू क्रांति का शंखनाद किया है? क्या यह आगामी विधानसभा चुनावों में हिंदू वोटों को एकत्र करने का नया एजेंडा है, या पश्चिम बंगाल में लगातार हिन्दुओं पर हो रहे हमलों, उनको कुचलने की कुचेष्टाओं एवं मुस्लिम तुष्टीकरण का माकुल जबाव है। बाबा बागेश्वर धाम-धीरेन्द्र शास्त्री सहित अनेक हिंदू धर्मगुरुओं के प्रवचनीय हस्तक्षेप, लाखों लोगों द्वारा सामूहिक गीता पाठ और संतों की हुंकार से एक नई चेतना आकार लेती दिखाई दे रही है। यह उभार महज आस्था का नहीं, बल्कि पहचान, सुरक्षा और गौरव के भावों का उभार है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाना मानो एक सोए हुए राक्षस को जगाने जैसा है, क्योंकि यह केवल एक मस्जिद का प्रश्न नहीं बल्कि देश की एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द की कसौटी है। सदियों से चला आ रहा बाबरी विवाद भारत की सामाजिक चेतना पर गहरे जख्म छोड़ चुका है-जिसने राजनीति को उग्र बनाया, समुदायों को बाँटा और नफरत व हिंसा के बीज बोए। ऐसे समय में जब राष्ट्र विभिन्न संकटों से जूझ रहा है, इस विवाद को नए भूगोल में स्थानांतरित कर हवा देना सामाजिक सामंजस्य एवं राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हो सकता है। सद्भाव और शांति की बुनियाद पर खड़े भारत को ऐसे मुद्दों की आवश्यकता है जो एकता को मजबूत करें, न कि पुराने घाव कुरेदकर समाज में तनाव और अविश्वास पैदा करें। अतः आवश्यक है कि नेतृत्व इस संवेदनशील विषय को विवेक, संवाद और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर संभाले, ताकि भारत का बहुलतावादी चरित्र और साझा सभ्यता सुरक्षित रह सके।

निश्चित ही बाबरी मस्जिद विवाद को हवा देकर कुछ मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक

वर्गों ने तनाव का वातावरण खड़ा किया है। इन दो समानांतर धाराओं की टकराहट ने बंगाल को विमर्श के केंद्र में ला दिया है कि क्या राज्य में हिंदू संगठित होकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हिन्दू-विरोधी साजिशों एवं षडयंत्रों का अंत चाहते हैं? बंगाल परंपरा से बौद्धिक और सांस्कृतिक बहुलता का प्रदेश रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में हिंदू सामाजिक मानस में एक बदलाव दिख रहा है। "गजवा हिंद" के प्रलापों के प्रतिकार में "भगवा हिंद" का संकल्प उभर रहा है। पांच लाख से अधिक हिंदुओं द्वारा एक साथ गीता पाठ करना इसी उभार का संकेत है, जिसमें धर्म प्रदर्शन शक्ति और अस्मिता के रूप में सामने आता है। साध्वी ऋतंभरा के वक्तव्यों ने इस उभार को एक नया स्वर दिया है। उनका स्पष्ट कथन कि "यह धरती प्रभु श्रीराम की है और श्रीराम की ही रहेगी" बंगाल सहित पूरे देश के हिंदू मानस में गूंज रहा है। यह कथन सिर्फ आस्था की घोषणा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अधिकार और आधिपत्य की अनुभूति का उद्घोष है। उनके भाषणों में उभरती चेतावनी है कि यदि हिंदू अपनी संस्कृति, परंपरा और मंदिरों की रक्षा के लिए नहीं उठे तो इतिहास स्वयं उनसे जवाब मांगेगा।

इस पृष्ठभूमि में बाबरी विवाद का पुनर्स्मरण राजनीति का साधन भी प्रतीत होता है। मुस्लिम संगठनों द्वारा इसकी मांगों को आगे बढ़ाना और नेताओं द्वारा इसे मुद्दा बनाना निश्चित ही सामाजिक भावना को चुनौती देता है। इसका प्रतिउत्तर धार्मिक मंचों से आया है, जहां प्रवचनों और सभाओं ने इसे हिंदू गौरव और अस्तित्व के प्रश्न के रूप में चित्रित किया है। ऐसे में यह कहना असंगत नहीं कि बंगाल की जमीन पर हिंदू पहचान की राजनीति तेजी से आकार ले रही है और हिन्दू धर्मगुरुओं के स्वर इसे वैचारिक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। उनका यह कथन कि "राम का नाम अनंत है, पर पुरुषार्थ के बिना सिर्फ नाम से रामराज्य नहीं आएगा" एक सीधा संकेत है कि हिंदू समाज को संगठित, सक्रिय और आत्मनिर्भर होना होगा। इस व्यापक परिदृश्य का मुख्य केंद्रबिंदु राजनीति है। क्या यह सब आगामी विधानसभा चुनावों का संकेत है? बंगाल की राजनीति लंबे समय से मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका के आसपास घूमती रही है और ममता बनर्जी ने मुस्लिम समाज के भरोसे को अपने समर्थन की नींव बनाया है। परंतु यदि हिंदू मतदाता नए सांस्कृतिक उभार से प्रेरित होकर एकजुट होते हैं, तो पहली बार बंगाल की सत्ता-समीकरण बदल सकते हैं। भाजपा और संघ परिवार का प्रयास भी इसी दिशा में है कि धार्मिक सम्मेलनों को राजनीतिक चेतना का मंच बनाकर हिंदू अस्मिता को वैचारिक शक्ति प्रदान करना। भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और धार्मिक प्रवचनीय हस्तक्षेपों द्वारा बंगाल में हिंदू एकता और पहचान को जागृत करने की रणनीति अपनाई जा रही है। इस राजनीतिक परिपाटी में बाबा बागेश्वर जैसे मंच प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, धर्म-सम्मेलनों को राजनीतिक चेतना की पाठशाला में बदला जा रहा है। साध्वी ऋतंभरा का बंगाल में सक्रिय होना उसी रणनीति की कड़ी है, क्योंकि उनका सशक्त भाषण हिंदू भावनाओं को झकझोरता है। बंगाल जिसकी पहचान बौद्धिक विनम्रता, कविता, महात्म्य और सहिष्णुता से जुड़ी रही है, वह अब टकराव, ध्रुवीकरण और प्रतिआक्रामकता की ओर बढ़ता दिख रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में भावनात्मक आवेश बढ़ रहा है और नेताओं द्वारा इस माहौल को चुनावी लाभ के लिए साधने की त्रासद कोशिशें तेज हैं। यह परिस्थिति बंगाल के सामाजिक ताने-बाने के लिए चुनौतीपूर्ण है।

फिर भी एक बात निर्विवाद है-बंगाल में एक नई चेतना, एक नई आकांक्षा जन्म ले रही है। यह पूर्ण क्रांति है या क्रांति का शंखनाद, यह कहना अभी जल्दबाजी होगा, परन्तु प्रारंभिक संकेत स्पष्ट हैं। हिंदू पहचान की राजनीति बंगाल में निर्णायक होती जा रही है, मुस्लिम वोट-बैंक की राजनीति पहली बार चुनौती में दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी की सत्ता को सांस्कृतिक विरोध का नया मोर्चा मिला है। अब यह समय बताएगा कि यह उभार सत्ता बदलता है या सामाजिक संवाद को बदलता है। लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति अब केवल विकास, योजनाओं और नेतृत्व की नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और प्रभुत्व की राजनीति बन चुकी है। यही कारण है कि धार्मिक मंचों की आवाज़ें चुनावी मैदान की धड़कन बन रही हैं। बंगाल अपने निर्णायक मोड़ पर खड़ा है-जहाँ राम का दावा और राम की भूमि का संकल्प राजनीति, समाज और भविष्य तीनों को प्रभावित करने वाला तत्व बन चुका है। न केवल मुस्लिम तुष्टिकरण बल्कि भ्रष्टाचार से लेकर मनमर्जी एवं तानाशाही का शासन चलाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रक्रिया बन गयी है। ममता वोट बैंक की राजनीति के लिये कानून की धज्जियां बार-बार उड़ाती रही है। ममता बनर्जी का एकमात्र लक्ष्य मुसलमानों के वोट बैंक को बरकरार रखना रह गया है। मुद्दा चाहे रोहिंग्या मुसलामानों के अवैध प्रवेश का हो या फिर बांग्लादेशियों का या अब बाबरी मस्जिद का। इसके लिए ममता ने देश की एकता-अखंडता और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया है, कानून से खिलवाड़ जितना पश्चिमी बंगाल में हुआ है उतना शायद ही देश के किसी दूसरे राज्यों में हुआ हो। तृणमूल कांग्रेस हिन्दुओं को पश्चिम बंगाल में सेकेंड क्लास सिटिज़न एवं अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की उसकी सोच एवं नीति न केवल उनके घोषणा-पत्रों में बल्कि उनके बयानों में स्पष्ट झलकती रही है। ममता ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, तृणमूल कांग्रेस का एकतरफा रवैया हमेशा से समाज को दो वर्गों में बांटता रहा है एवं सामाजिक असंतुलन तथा रोष का कारण रहा है। बदले हुए राजनीतिक हालात इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किसी भी एक वर्ग की अनदेखी कर कोई भी दल राजसत्ता का आनंद नहीं उठा सकता। पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है वह महज 'बागेश्वर बनाम बाबरी विवाद' नहीं है, यह सांस्कृतिक-धार्मिक पुनर्स्थापन की कोशिश बनाम राजनीतिक मुस्लिम केंद्रवाद की प्रतिस्पर्धा है। अभी के लिए, बंगाल की जमीन पर धर्म, राजनीति और पहचान का नया त्रिकोण उभर चुका है और वही आने वाले समय में बंगाल की राजनीतिक दिशा, सामाजिक संबंधों और सत्ता के समीकरणों को आकार देगा।

प्रेरणा

जहाँ हृदय की थरथराती लहरें आत्मा के गहरे तल में स्थिर हो जाती हैं

वॉल्टेयर के जीवन की एक सुबह किसी पुराने संगीत की तरह धीमी और स्थिर थी। आकाश में बादल धूप को चूमकर आगे बढ़ रहे थे। शहर की गलियों में हल्की ठंड थी, पर वातावरण में एक विचित्र-सी ऊर्जा तैर रही थी। उसी ऊर्जा को चीरता हुआ एक युवा विद्वान तेज़ कदमों से वॉल्टेयर के निवास की ओर बढ़ रहा था। उसकी आँखों में बेचैनी थी, चेहरे पर उलझन, और मन में गहरी थकान। वह ज्ञान की तलाश में था, पर ज्ञान ही उसके लिए बोझ बन चुका था।

वॉल्टेयर अपने घर के पत्थरों से बने पुराने आँगन में बैठे थे। उनके सामने एक अधखिली गुलाब की कली तैरती हवा में हल्का-सा कांप रही थी। जब युवक वहाँ पहुँचा, वह बिना औपचारिकता के सीधे बोला—"सर, मैं दुनिया को समझना चाहता हूँ—दर्शन पढ़ रहा हूँ, इतिहास पढ़ रहा हूँ, विज्ञान पढ़ रहा हूँ। पर जितना पढ़ता हूँ, उतना ही भ्रम बढ़ता है। मन शांत नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे पूरा जगत एक प्रश्नचिह्न बनकर मेरे सामने खड़ा है।"

वॉल्टेयर ने उसे निहारते हुए अपनी उंगलियों से मेज पर पड़े एक सूखे पत्ते को घुमाया। उन्होंने गहरी साँस ली और बिना कुछ कहे उसे इशारे से पीछे आने को कहा। दोनों घर के पिछवाड़े पहुँचे। वहाँ एक बाग था—न छोटा, न बड़ा—पर उसके भीतर प्रकृति का गहन रहस्य छुपा था। पेड़ हवा में झूम रहे थे, फलदार पौधे अपनी गति से बढ़ रहे थे। कहीं फूल खिले थे, कहीं पत्ते सूखकर नीचे गिर रहे थे।

युवक ने बाग़ को देखा और तुरंत बोला—"यहाँ कुछ पौधे घने और सुंदर हैं, पर कुछ तो बिल्कुल जीवित भी नहीं लग रहे।"

वॉल्टेयर मुस्कुराए—एक ऐसी मुस्कान जो ज्ञान से कहीं अधिक अनुभव की गवाही देती थी। उन्होंने मिट्टी को छूकर कहा—"यह बाग़ कभी शिकायत नहीं करता। इसे फर्क नहीं पड़ता कि किस पौधे के कितने फूल हैं, कौन-सा पौधा आज मजबूत है और कौन-सा कमजोर। प्रकृति खुद जानती है कि हर पौधा अपनी लय से बढ़ता है—कोई तेज़, कोई धीमे, कोई मुरझाता है, कोई फिर से खिल उठता है। लेकिन यह पूरा बाग़—अपनी अपूर्णताओं के बावजूद—सुंदर है।"

युवक ने धीमे स्वर में पूछा—"लेकिन सर, इसका ज्ञान से क्या संबंध है?"

वॉल्टेयर धीरे-धीरे बाग़ की पगडंडी पर चलते हुए बोले—"तुम दुनिया को एक ही दिन में समझ लेना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सारे पौधे एक ही दिन फूल दे दें, सारी पत्तियाँ कभी न झरें, और हर बीज हर मौसम में उग आए।

पर ऐसा नहीं होता।

जैसे मिट्टी उतना ही पानी सह सकती है जितना उसके लिए आवश्यक है, तुम्हारा मन भी उतना ही ज्ञान संभाल सकता है जितना वह एक दिन में ग्रहण कर सके।"

युवक कुछ क्षण चुप रहा। हवा की एक हल्की लहर चली और पेड़ों की पत्तियाँ सरसराकर बात करने लगीं।

वॉल्टेयर आगे बोले—"ज्ञान को मजबूर करने से वह उलझन बन जाता है। तुम जितना पढ़ते जा रहे हो, उतना ही मन में दुःख, बेचैनी और भ्रम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तुम धैर्य नहीं रख पा रहे। तुम चलते हुए बाग़ में फूल खोज रहे हो, पर पता नहीं तुम्हें जड़ों के लिए समय देना चाहिए था।"

युवक ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर का तनाव हिल रहा है—जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा धीरे-धीरे पिघलने लगा हो।

वॉल्टेयर ने आकाश की ओर देखा—"जीवन कोई दावत नहीं जहाँ सबकुछ एक साथ परोसा जाता है। यह नदी की तरह है—धीरे-धीरे आगे बढ़ती हुई, कभी शांत, कभी तेज़, कभी गहरी, कभी सतही। तुम नदी को समझ सकते हो, पर उसके बहाव को झटके से पकड़ नहीं सकते। ज्ञान का रास्ता वही है जहाँ हर दिन थोड़ा-सा कदम बढ़ाया जाए। आज जो समझ न आए, वह कल आएगा। पर अगर आज ही सबकुछ पकड़ने की कोशिश करोगे, तो मन टूट जाएगा, जैसे तेज़ हवा में पतंग की डोर टूट जाती है।"

युवक की आँखों से बेचैनी उतर रही थी। वह महसूस कर रहा था कि बाग़ का हर पौधा, हर फूल, हर सूखा पत्ता उसे कुछ सिखा रहा है। दुनिया को समझने का बोझ उसके सिर से उतर रहा था—मानो किसी ने उसकी आत्मा पर रखे भारी पत्थर को धीरे से हटा दिया हो।

वॉल्टेयर ने अंत में कहा—"दुनिया को समझने की कुंजी ज्ञान नहीं—धैर्य है। ज्ञान तो समय के साथ खुद प्रकट होता है, पर धैर्य वही दीपक है जो उसके आने तक अंधेरे को रोके रखता है। जिसने धैर्य को पकड़ लिया, उसने दुनिया को समझने की आधी यात्रा पूरी कर ली।"

युवक ने सिर झुकाया। अब उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। उसके भीतर एक शांत सरोवर बन चुका था—स्थिर, गहरा और शीतल।

उसे पहली बार अहसास हुआ कि समझ अचानक बिजली की तरह नहीं चमकती—वह तो सुबह की ओस की तरह गिरती है, बूंद-बूंद, और जब मन तैयार होता है, तभी उसे महसूस कर पाता है।

उस दिन युवक जब वापस लौटा, उसके साथ कोई भारी ज्ञान नहीं था—बस एक हल्का-सा प्रकाश, जो उसके जीवन के हर मोड़ पर जगमगाता रहेगा।

वह प्रकाश था—अनुभूति का शांत सरोवर।

ऑपरेशन सिंदूर के 'रील वर्जन' धुरंधर से आखिर क्यों डर गये कुछ मुस्लिम देश?

हिंदी फिल्म धुरंधर को लेकर जो बवंडर उठा है, वह सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं है बल्कि यह उस बदलती दुनिया की कहानी है जहाँ भारत का पक्ष मज़बूती से उभर रहा है और कुछ देशों को यह हक़ीक़त पच नहीं रही है। सबसे पहले एक बात साफ है कि धुरंधर कोई फैंटेसी नहीं है, यह एक रील रूप है उस हकीकत का, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई के जरिए दुनिया के समक्ष रखा है। यही वजह है कि पाकिस्तान और उसके समर्थकों के दिल में यह फिल्म काँटे की तरह चुभ रही है। लेकिन असली सवाल पाकिस्तान से भी बड़ा है। भारत के दोस्त कहे जाने वाले खाड़ी देश आखिर पाकिस्तान की राय से इतने प्रभावित क्यों हैं कि उन्होंने फिल्म को सीधे-सीधे बैन कर दिया? यह वही खाड़ी देश हैं जिनके साथ भारत आज रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा सहयोग, व्यापार और सुरक्षा रिश्ते मजबूत कर चुका है। फिर सिर्फ इसलिए कि एक फिल्म पाकिस्तान के इस्लामवादी ढांचे को बेनकाब करती है, वह भारत के पक्ष की बजाय पाकिस्तान के दबाव में क्यों झुक गए? क्या दोस्ती इतनी कमजोर थी? या यह डर कहीं गहरा बैठा है कि भारत का मजबूत नैरेटिव मुसलमानों के नाम पर राजनीति चलाने वाले देशों को असुविधा में डाल देता है?

खाड़ी देशों की यह स्थिति एक और सच्चाई उजागर करती है कि भारत जब अपने मन की कहानी कहने लगता है, तो दुनिया के कई शक्ति-केन्द्र असहज होने लगते हैं। चूंकि यह कहानी अब किसी पश्चिमी देश ने नहीं, बल्कि भारत ने लिखी है और वह भी बेबाकी के साथ इसलिए इसे 'संवेदनशील', 'विवादास्पद' और 'राजनीतिक' कहकर दबाने की कोशिश हो रही है। देखा जाये तो हॉलीवुड की फिल्में जब नाज़ियों पर चलती थीं या आतंकियों पर बनती थीं, तब किसी को समस्या नहीं थी। Inglourious Basterds या Zero Dark Thirty पर किसी खाड़ी देश ने बैन नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही भारत उसी भाषा में अपना सच बोलता है तो कुछ देशों को मानो बुखार चढ़ जाता है।

असल बात यह है कि अगर रील में दिखाई गई भारत की शक्ति से ही इतनी घबराहट है, तो असली भारत का सामना करने का साहस कहाँ से आएगा? आज का भारत वह नहीं रहा जिसे डराया जा सके या जिसकी आवाज़ रोकी जा सके। यह नया भारत अपने सैनिक अभियान भी दिखाता है, आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति भी स्पष्ट रखता है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर किसी के लिहाज में झुकता नहीं। खाड़ी देशों को यह समझ लेना चाहिए कि इस भारत के साथ खड़ा होना फायदे का सौदा है और पाकिस्तान जैसे असफल, कट्टरतावादी ढाँचे को खुश करने के लिए भारत से दूरी बनाना भविष्य में उन्हें और महंगा पड़ेगा।

फिल्म धुरंधर को लेकर जो हंगामा हो रहा है, वह यह साबित करता है कि पाकिस्तान का नैरेटिव अब कमजोर हो रहा है और भारत का नैरेटिव ताकत पकड़ रहा है। वह देश जो पाकिस्तान के पारंपरिक प्रभाव में थे, वह इस बदलाव को देखकर घबराए हुए हैं। लेकिन घबराहट से ज्यादा यह उनकी कमजोरी दिखाती है क्योंकि सच्चाई से डरने वाले ही आवाज़ों को दबाते हैं। दूसरी ओर, भारत को इस बहिष्कार से विचलित होने की जरूरत नहीं है। बल्कि यह तो संकेत है कि भारत की सांस्कृतिक और रणनीतिक ताकत सीधे सही जगह चोट कर रही है। अगर सिर्फ एक फिल्म से इतनी बेचैनी है, तो भारत के वास्तविक संकल्प और शक्ति का असर कितना गहरा होगा, यह दुनिया अच्छी तरह समझ चुकी है। इसलिए, पाकिस्तान और उसके प्रभाव में चलने वाले देशों को एक सलाह है कि डरते रहिए। क्योंकि नए भारत की राह में अब न आपका नैरेटिव चलेगा, न आपकी शर्तें। अब भारत अपनी कहानी खुद लिखता है और पूरी दुनिया उसे सुनने को मजबूर है।

अभियान

जो मन की आँधियों में भी बुझता नहीं और आत्मा के अँधेरों में अपना स्वर्णिम प्रकाश स्वयं रचता है

धैर्य की यह कथा जितनी सरल दिखती है, उतनी ही गहरी है, और जब इसे पूरी तरह विस्तृत रूप में कहा जाए, तो यह मन की एक लंबी यात्रा बन जाती है—एक ऐसी यात्रा, जिसमें प्रश्नों का कोलाहल धीरे-धीरे शांत होकर अनुभव का संगीत बन जाता है।

एक बार का प्रसंग है। पेरिस की ठंडी सुबह थी। आसमान धुंध से भरा हुआ था, और गलियों में हल्की नमी तैर रही थी। एक युवा विद्वान, जो अपने ज्ञान के अहंकार और भ्रम के बोझ दोनों से झुका हुआ था, वॉल्टेयर के घर पहुंचा। साहित्य, दर्शन और बुद्धि के मंदिर कहे जाने वाले वॉल्टेयर से मिलने का अवसर उसे संयोग से मिला था। पर युवक का मन अस्थिर था, जैसे जलधारा में कंकड़ गिरने से पैदा हुई छोटी लहरें, जो थोड़ी देर में शांत होने के बजाय और ज्यादा फैल जाती हैं।

वह वॉल्टेयर के सामने बैठा और बिना भूमिका के बोल पड़ा,

"सर, मैं इस दुनिया को समझने आया हूँ पर समझ जितनी बढ़ती है, उतना ही मन उलझता जा रहा है। मैं जितना पढ़ता हूँ, उतना और अंधेरा महसूस करता हूँ। क्या ज्ञान का कोई अंत है? क्या कभी मन पूरी तरह शांत हो सकता है?"

वॉल्टेयर ने युवक को गहरी, ठहरी हुई दृष्टि से देखा। फिर बिना कुछ कहे उठे और उसे अपने घर के पीछे बने बाग में ले गए। यह बाग किसी राजा के बाग की तरह भव्य नहीं था, पर इसकी

सादगी में एक दिव्यता थी। हल्की धूप पेड़ों के बीच से छिटककर आ रही थी, पत्तों पर ओस अब भी चमक रही थी, और हवा में एक शांत, धीमी सुगंध तैर रही थी।

वहां कई प्रकार के पौधे थे—कुछ हरे-भरे, कुछ मुरझाए, कुछ फूलों से भरे हुए, और कुछ केवल सूखी शाखें रह गए।

वॉल्टेयर ने पूछा,

"तुम्हें क्या दिख रहा है?"

युवक ने बिना सोचे कहा,

"कुछ पौधे खूब फल-फूल रहे हैं, और कुछ बिल्कुल सूखे हैं। लगता है जैसे कुछ को देखभाल मिली, और कुछ को नहीं।"

वॉल्टेयर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनुभव की रोशनी थी, जो शब्दों से ज्यादा बोलती थी। उन्होंने मिट्टी को छुआ, अपनी उंगलियों से उसके कणों को महसूस किया और बोले,

"क्या तुमने कभी इस बाग को शिकायत करते सुना है? क्या यह कहता है कि एक फूल कम है, या यह कि किसी शाख का रंग फीका हो गया? नहीं। बाग बस अपना काम करता है—जो जीवित है, उसे जीवन देता है; जो सूख गया है, उसे धीरे-धीरे मिट्टी में लौटने देता है।"

फिर वे युवक की ओर मुड़े।

"दुनिया भी एक ऐसा ही बाग है। और मन—उस बाग का माली।"

युवक उनकी बात सुनकर कुछ समझा, कुछ उलझा।

"लेकिन सर, ज्ञान तो सबकुछ समझ लेने का नाम है, है न?"

वॉल्टेयर ने चलना शुरू किया, और युवक उनके पीछे-पीछे।

"नहीं," उन्होंने धीरे से कहा, "ज्ञान सबकुछ जान लेने का नाम नहीं। ज्ञान यह जान लेने का नाम है कि कब रुकना है, और कब समझ को बढ़ने देना है।

जिस प्रकार पौधों को हर दिन थोड़ा-थोड़ा पानी चाहिए—न बहुत ज्यादा, न बहुत कम—उसी तरह ज्ञान को भी समय चाहिए। धैर्य चाहिए।"

कुछ कदम बाद वे एक छोटे, कमजोर पौधे के पास रुके।

यह पौधा बाँझ मिट्टी में लगा था, और बहुत धीमी गति से बढ़ रहा था।

वॉल्टेयर ने उसे हल्के से छुआ और कहा,

"देखो, यह पौधा मजबूत नहीं है—पर यह अपना पूरा प्रयास कर रहा है। अगर मैं इसे जबरन खींचकर बड़ा करने की कोशिश करूँ, तो यह टूट जाएगा।"

फिर युवक की ओर देखकर बोले,

"तुम भी ज्ञान को खींचकर बड़ा करना चाहते हो। तुम सब कुछ एक ही दिन समझ लेना चाहते हो। यही भ्रम का कारण है। ज्ञान एक-एक बूंद की तरह मन में उतरता है। जो उसके रास्ते को धैर्य से स्वीकार करता है, वही भीतर से प्रकाशित होता है।"

युवक की आंखों में पहली बार कोमल समझ की रोशनी आई।

धीरे से बोला,

"तो समाधान क्या है?"

वॉल्टेयर ने कहा,

"जो चीज तुम्हारे हाथ में है—उसे संवारो। जो नहीं है—उसे जाने दो।

दुनिया को एक ही बार में समझने की कोशिश मत करो। हर दिन थोड़ा सीखो। हर अनुभव को उसकी गति से बढ़ने दो। धैर्य वह प्रकाश है, जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता।"

बाग से लौटते-लौटते युवक का मन बदल चुका था।

वह जब आया था—उसके भीतर तूफान था।

अब लौटते समय—शांति की एक धीमी, स्थिर रोशनी।

उसने महसूस किया कि ज्ञान बाहर की चीज नहीं, अंदर का सूर्योदय है।

और वह सूर्योदय तभी होता है, जब मन धैर्य की सुबह को स्वीकार करता है।

इस तरह वॉल्टेयर की एक छोटी यात्रा ने युवक को जीवन भर का प्रकाश दे दिया—यह सत्य कि

पूर्वज्ञान नहीं धैर्य ही सच्चा दीपक है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विभिन्न शिक्षा योजनाओं के तहत 13 लाख से अधिक छात्रों को 370 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सहायता वितरित की

▶▶ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शिक्षा मंत्री श्री प्रद्युमन वाजा और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा की प्रेरक उपस्थिति

▶▶ नमो लक्ष्मी योजना, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए सहायता वितरित

▶▶ बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरा हो रहा है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ राज्य सरकार ने अनेक शैक्षणिक योजनाएं कार्यरत कीं, ताकि छात्रों पर आर्थिक बोझ न पड़े : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▶▶ शिक्षा में किया गया निवेश केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि विकसित गुजरात के निर्माण की मजबूत नींव है : शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा

(जीएनएस)। गांधीनगरः मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, शिक्षा मंत्री श्री प्रद्युमन वाजा और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा की उपस्थिति में नमो लक्ष्मी योजना, नमो सरस्वती विज्ञान साधना, मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के 13 लाख से अधिक लाभार्थी छात्रों को 370 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए हस्तांतरित की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पिछले ढाई दशक में राज्य में शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री का बच्चों को केजी से पीजी तक की शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराने का लक्ष्य साकार हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद छात्र माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा भी सफलतापूर्वक पूर्ण करें तथा कन्या शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन मिले, इसकी चिंता करते हुए नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजनाएं शुरू की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'बेटी बचाओ' अभियान के जरिए देश में बेटियों की शिक्षा को काफी बड़ी गति दी है। श्री पटेल ने कहा कि जब उन्होंने 2001 में गुजरात का सेवादायित्व संभाला, तब अनेक समस्याएं थीं। श्री नरेन्द्र मोदी ने ऐसे समय में देश में एक उदाहरण पेश किया कि, किस प्रकार एक राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं गांव-गांव जाकर बेटियों

की शिक्षा का सेवा-यज्ञ शुरू करता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री उन्हें मिलने वाले उपहारों की नीलामी करके उससे प्राप्त होने वाली राशि को कन्या केळवणी (शिक्षा) के लिए देने की एक नई परंपरा शुरू की। इन सभी के परिणामस्वरूप लोगों में भी बेटियों को स्कूल भेजने की जागरूकता बढ़ी और शाला प्रवेशोत्सव-कन्या केळवणी महोत्सव की सफलता के चलते बेटियों के ड्रॉपआउट की दर 37 फीसदी से घटकर 2 फीसदी से भी नीचे आ गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब गांवों में विज्ञान संकाय के स्कूलों की संख्या बहुत ही कम थी जबकि आज विज्ञान संकाय के स्कूलों की संख्या 2834 हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि 2001 में केवल 775 कॉलेज थे, आज गुजरात में 3200 से अधिक कॉलेज छात्रों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा 12 में विज्ञान संकाय के बाद इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिए जाना हो, तो केवल 139 कॉलेज थे, आज इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 288 पर पहुंच गई है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवादायित्व संभाला तब 1175 मेडिकल सीटें थीं, जो आज बढ़कर 7000 से अधिक हो गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल में पढ़ाई करने वाली बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि योजना से अब तक राज्य की 24 हजार से अधिक बेटियों को सहायता प्रदान की गई है।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात और देश का भविष्य जिनके हाथों में हैं, ऐसे आज के छात्रों के लिए गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई फ्लैगशिप योजनाओं में से चार योजनाओं के अंतर्गत आज 13 लाख से अधिक छात्रों के बैंक खातों में सीधे 370 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति सहायता डीबीटी के जरिए भेजी गई है। अब तक, राज्य सरकार ने इन चारों योजनाओं के अंतर्गत कुल 13.50 लाख से अधिक छात्रों को 1332 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है।

श्री हर्ष संघवी ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को उनके दूसरे कार्यकाल के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नागरिकों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं और अपने स्वभाव के अनुसार सौम्यता के साथ पूरे मंत्रिमंडल की टीम को भी इसी प्रकार जनहित के निर्णय लेने के लिए लगातार प्रेरणा, छूट और हिम्मत दी है। शिक्षा विभाग की जिन चार योजनाओं के तहत आज छात्रवृत्ति सहायता दी गई है, उनमें से एक फ्लैगशिप योजना भी उनके ही निर्णय का हिस्सा है। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस प्रकार के प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहकर मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिखाया है कि शिक्षा विभाग और हमारे भविष्य इन छात्रों के लिए उनका कितना समर्पण और योगदान है।

श्री संघवी ने नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के बारे में कहा कि गुजरात में जिस तरह से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ऐसे में यह जरूरी है कि हमारे छात्र भी उसमें अपना योगदान दे सकें। यदि कोई माता-पिता अपने बच्चे को विज्ञान संकाय में पढ़ाना चाहते हों, तो उन पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े, इन नेक विचारों के साथ राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसका राज्य के अनेक छात्र लाभ उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने छात्रवृत्ति वितरण के अवसर पर कहा कि गुजरात सरकार विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण में शिक्षित और सक्षम समाज का निर्माण करने के लिए अडिग है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग देश का भविष्य यानी आज के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए योग्य दिशा देने को संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा में किया गया यह निवेश केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आने वाले समय के विकसित गुजरात के निर्माण की मजबूत नींव है। ये महत्वपूर्ण कदम गुजरात के छात्रों के जीवन को एक नई दिशा, नए अवसर और नए सपने देंगे।

गुजरात सरकार द्वारा शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली चार महत्वपूर्ण योजनाओं से आ रहे बदलावों की चर्चा करते हुए श्री वाजा ने कहा कि इन योजनाओं से लाखों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हो रहा है। नमो लक्ष्मी योजना बेटियों के सशक्तिकरण का शक्तिशाली माध्यम बनी है। इस योजना के तहत अब तक 10.49 लाख बेटियों को डीबीटी के जरिए 1033 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। इसके चलते बेटियों की उपस्थिति में 73 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा कक्षा 12 में प्रवेश लेने वाली बेटियों की संख्या में 13.59 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के माध्यम से विज्ञान संकाय में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए 1.5 लाख छात्रों को 151.84 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जिससे विज्ञान संकाय के नामांकन में 6.34 फीसदी की वृद्धि हुई है। मेरिट और गुणवत्ता पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने वाली अन्य दो योजनाएं- मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 50,000 छात्रों को 86.14 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना के तहत 60,000 छात्रों को 61.27 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि ये चारों योजनाएं गुजरात के लाखों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए ज्ञानसेतु का निर्माण कर रही हैं।

शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रीवाबा जाडेजा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उद्धृत करते हुए कहा कि शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव और प्रत्येक बालक को सशक्त बनाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस विचार को साकार करने वाले आज के कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा 13 लाख से अधिक छात्रों को डीबीटी के जरिए 370 करोड़ रुपए की सहायता पहुंचाने का यह एक ऐतिहासिक अवसर है।

श्रीमती जाडेजा ने आगे कहा कि हमारे देश का प्रत्येक बालक उज्ज्वल भारत का स्वप्न है, इसलिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती सहित अनेक योजनाओं के जरिए बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर लगातार कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही आधारभूत सुविधाओं में लगातार वृद्धि करना, कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना, ड्रॉपआउट अनुपात को कम करना और बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ राज्य के छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान कर सुंदर भविष्य बनाने का प्रयास करना है।

कार्यक्रम में गांधीनगर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिल्पाबेन पटेल, महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगर शहर संगठन प्रमुख डॉ. आशीष दवे, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री मुकेश कुमार, निदेशक, स्कूल कार्यालय श्री प्रजेश राणा, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।

रेल सुरक्षा रिकॉर्ड सुधार में वृद्धि : वार्षिक दुर्घटनाएं 2004-14 के औसत 171 से घटकर 2025-26 में अब तक 11 रह गई हैं

▶▶ सुरक्षा बजट लगभग तीन गुना बढ़कर 2013-14 के 39,463 करोड़ रूपए से चालू वित्त वर्ष में 1,16,470 करोड़ रूपए हो गया है

▶▶ अश्विनी वैष्णव ने कहा- कोहरे से बचाव के उपकरणों की संख्या 288 गुना बढ़ी है — 2014 के 90 से बढ़कर 2025 में 25,939 हो गई है

▶▶ पिछले चार महीनों में 21-21 स्टेशनों पर केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और ट्रैक-सर्किट का काम पूरा हो गया है

(जीएनएस)। भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी असामान्य घटना की रेलवे प्रशासन द्वारा गहन जांच की जाती है। तकनीकी कारणों के अलावा किसी अन्य कारण की आशंका होने पर राज्य पुलिस की सहायता ली जाती है।

कुछ मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से भी मार्गदर्शन लिया जाता है। हालांकि, जांच का प्राथमिक माध्यम राज्य पुलिस ही है। यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। इसके अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों की जांच, कानून व्यवस्था बनाए रखना और पटरियों, पुलों, सुरंगों आदि रेलवे के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

वर्ष 2023 और 2024 में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़/तोड़फोड़ की सभी घटनाओं में, राज्यों की पुलिस/जीआरपी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मामले दर्ज किए गए। इसके बाद जांच, अपराधियों की गिरफ्तारी की गई और उन पर मुकदमा चलाया गया।

रेलवे द्वारा राज्य पुलिस/जीआरपी के साथ बेहतर समन्वय, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए समन्वित कार्रवाई और निगरानी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

▶▶ चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों और असुरक्षित इलाकों में रेलकर्मियों, रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और सिविल पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से लगातार गश्त की जा रही है।

▶▶ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, असुरक्षित इलाकों में गश्त करने और खतरों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने हेतु विशेष दल गठित किए गए हैं।

▶▶ रेलवे पटरियों के पास पड़ी सामग्री को हटाने के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका उपयोग शरारती तत्व रेलवे ट्रैक पर रखकर अवरोध उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं।

▶▶ रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले लोगों को ट्रैक पर अवांछित सामग्री रखने, रेल घटकों को हटाने के बाद होने वाली संभावित घटनाओं के परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है और उनसे सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का अनुरोध किया जा रहा है।

▶▶ रेलवे राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इनका गठन प्रत्येक राज्य में सम्बंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया है। इसमें रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और खुफिया इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अपराध पर नियंत्रण, मामलों के पंजीकरण, उनकी जांच और रेलवे परिसर के साथ-साथ चलती ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरपीएफ द्वारा राज्य पुलिस/जीआरपी अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से घनिष्ठ संपर्क स्थापित किया जाता है। इसमें तोड़फोड़ की घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है और खुफिया जानकारी साझा की जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त के अलावा, स्थिति के अनुसार एनआईए और सीबीआई जैसी विशेष एजेंसियां भी शामिल हैं।

▶▶ केंद्रीय और राज्य खुफिया एजेंसियों के अलावा, आरपीएफ की खुफिया इकाइयां, यानी सीआईबी और एसआईबी को नियमित रूप से जागरूक किया जाता है और उन्हें निर्देश दिए जाते हैं कि वे खुफिया जानकारी एकत्र करें और पुलिस अधिकारियों के समन्वय से तोड़फोड़ के प्रयासों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

ट्रेन संचालन में सुरक्षा सुधारने के लिए भारतीय रेल द्वारा कई उपाय किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाए अनुसार, परिणामी ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या 2014-15 में 135 से घटकर 2024-25 में 31 हो गई है।

गौरतलब है कि 2004-14 की अवधि के दौरान परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या 1711 थी (औसतन 171 प्रति वर्ष), जो 2024-25 में घटकर 31 और 2025-26 में (नवंबर 2025 तक) और भी घटकर 11 रह गई।

पिछले पांच वर्षों के दौरान परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाई गई है:-

रेल संचालन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाए गए विभिन्न सुरक्षा उपाय इस प्रकार हैं:-

1.भारतीय रेल में सुरक्षा सम्बंधी गतिविधियों पर व्यय में पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित रूप से वृद्धि हुई है:-

सुरक्षा सम्बंधी गतिविधियों पर व्यय/बजट (रुपये करोड़ में)

2013-14	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
39,463	87,327	1,01,651	1,14,022	1,16,470

2.मानव विफलता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 31.10.2025 तक 6,656 स्टेशनों पर बिंदुओं और संकेतों के केंद्रीकृत संचालन के साथ विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाए गए हैं

3.लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेटों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 31.10.2025 तक 10,098 लेवल क्रॉसिंग गेटों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।

4.विद्युत माध्यम से ट्रैक की उपलब्धता की पुष्टि करके सुरक्षा बढ़ाने के लिए 31.10.2025 तक 6,661 स्टेशनों पर पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था की गई है।

5.कवच एक अत्यंत तकनीकी रूप से उन्नत प्रणाली है। इसके लिए उच्चतम स्तर के सुरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है। कवच को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया था। कवच को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। प्रारंभ में, कवच संस्करण 3.2 को दक्षिण मध्य रेलवे के 1465 आरकेएम और उत्तर मध्य रेलवे के 80 आरकेएम पर तैनात किया गया था। कवच विनिर्देश संस्करण 4.0 को आरडीएसओ द्वारा 16.07.2024 को मंजूरी दी गई थी। व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद, कवच संस्करण 4.0 को दिल्ली-मुंबई मार्ग पर पलवल-मथुरा-कोटा-नागदा खंड (633 किमी) और दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर हावड़ा-बर्दवान खंड (105 किमी) पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्ग के शेष खंडों में कवच का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे के सभी जीक्यू, जीडी, एचडीएन और चिन्हित खंडों को कवर करते हुए 15,512 किमी पर कवच का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है।

6.सिग्नलिंग की सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दों, जैसे अनिवार्य पत्राचार जांच, परिवर्तन कार्य प्रोटोकॉल, पूर्णता आरेखण तैयार करना आदि के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

7.एस एंड टी उपकरणों के लिए प्रोटोकॉल के अनुसार डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन की प्रणाली पर पुनः बल दिया गया है।

8.सभी लोकोमोटिव में लोको पायलटों की सतर्कता बढ़ाने के लिए विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस (वीसीडी) लगाए गए हैं।

9.कोहरे के कारण कम दृश्यता होने पर चालक दल को आगे के सिग्नल के बारे में सूचित करने के लिए विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिग्नल से दो ओएचई मास्ट आगे स्थित मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए गए हैं।

10.लोको पायलटों को सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट आदि जैसे निकटवर्ती स्थलों की दूरी का पता चल सके। इसके लिए कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों को जीपीएस आधारित कोहरे से सुरक्षा उपकरण (एफएसडी) प्रदान किया जाता है।

11.प्राथमिक ट्रैक नवीनीकरण के दौरान 60 किलोग्राम भार, 90 अल्टीमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ (यूटीएस) रेल, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) नॉर्मल/वाइड बेस स्लीपर (इलास्टिक फास्टनिंग के साथ), पीएससी स्लीपरों पर फैन शेप्ड लेआउट टर्नआउट और गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपरों से युक्त आधुनिक ट्रैक संरचना का उपयोग किया जाता है।

12.मानवीय गलतियों को कम करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आदि जैसी ट्रैक मशीनों के उपयोग के माध्यम से ट्रैक बिछाने की गतिविधि मशीनों से की जाती है।

13.रेल नवीनीकरण की प्रगति बढ़ाने और जोड़ों की वेल्डिंग से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे रेल पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना, जिससे सुरक्षा में सुधार हो सके।

14.रेलों में खामियों का पता लगाने और दोषपूर्ण रेलों को समय पर हटाने के लिए अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन (यूएसएफडी) परीक्षण।

15.लंबी रेलों की बिछावट, एल्युमिनो थर्मिक वेल्डिंग का न्यूनतम उपयोग और रेलों के लिए बेहतर वेल्डिंग तकनीक, जैसे फ्लैश बट वेल्डिंग को अपनाना।

16.ओएमएस (ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम) और टीआरसी (ट्रैक रिकॉर्डिंग कार) द्वारा ट्रैक ज्यामिति की निगरानी।

17.वेल्ड/रेल फ्रैक्चर की जांच के लिए रेलवे ट्रैक पर गश्त।

18.टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग का उपयोग।

19.कर्मचारियों को सुरक्षित प्रक्रियाओं के पालन के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण और प्रशिक्षण देना।

20.ट्रैक परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, जैसे ट्रैक डेटाबेस और निर्णय समर्थन प्रणाली, को तर्कसंगत रखरखाव आवश्यकताओं का निर्णय लेने और इनपुट को अनुकूलित करने के लिए अपनाया गया है।

21.एकीकृत ब्लॉक, कॉरिडोर ब्लॉक, कार्यस्थल सुरक्षा, मानसून के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां आदि ट्रैक की सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दों के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

22.रेलवे की संपत्तियों (कोच और वैगन) का निवारक रखरखाव सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

23.पारंपरिक आईसीएफ डिज़ाइन के कोचों को एलएचबी डिज़ाइन के कोचों से बदला जा रहा है।

24.ब्रॉड गेज (बीजी) रूट पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग (यूएमएलसी) जनवरी 2019 तक हटा दिए गए हैं।

25.रेलवे पुलों की सुरक्षा नियमित निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान पाई गई स्थिति के आधार पर पुलों की मरम्मत/पुनर्वास की आवश्यकता पर विचार किया जाता है।

26.भारतीय रेल ने सभी कोचों में यात्रियों की व्यापक जानकारी के लिए वैधानिक "अग्नि सम्बंधी नोटिस" प्रदर्शित किए हैं। आग से बचाव के लिए विभिन्न नियमों और सावधानियों के बारे में यात्रियों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए प्रत्येक कोच में अग्नि सम्बंधी पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें ज्वलनशील सामग्री, विस्फोटक न ले जाने, कोच के अंदर धूम्रपान निषेध, जुर्माने आदि से सम्बंधित संदेश शामिल हैं।

27.उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और पैंट्री कारों में अग्नि पहचान एवं शमन प्रणाली तथा नवनिर्मित कोचों में अग्नि और धुआं पहचान प्रणाली उपलब्ध करा रही हैं। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा मौजूदा कोचों में भी चरणबद्ध तरीके से इन प्रणालियों को लगाने का कार्य प्रगति पर है।

28. कर्मचारियों का नियमित रूप से परामर्श एवं प्रशिक्षण किया जाता है।

29. भारतीय रेल (खुली लाइनें) के सामान्य नियमों में 30.11.2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से रोलिंग ब्लॉक की अवधारणा को लागू किया गया है। इसके तहत परिसंपत्तियों के एकीकृत रखरखाव/मरम्मत/प्रतिस्थापन का कार्य 52 सप्ताह पहले तक रोलिंग आधार पर योजनाबद्ध किया जाता है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

वीसीई को राज्य सरकार के विभागों द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों के लिए प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में संवेदनशील निर्णय

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में कमीशन के आधार पर ग्राम कंप्यूटर उद्यमी (वीसीई) के तौर पर काम करने वाले युवाओं की अधिकतम आय सुनिश्चित करने वाला संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने इस संदर्भ में यह निर्णय किया है कि वीसीई को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सौंपे गए कार्यों के लिए प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा।

राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के जरिए शहरी क्षेत्र में उपलब्ध ई-सेवाओं जैसी ही सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराने के उद्देश्य से 'ई-ग्राम विश्वग्राम योजना' लागू की है। उल्लेखनीय है कि ग्राम कंप्यूटर उद्यमी (वीसीई), ग्राम स्तर पर लोगों को 7/12, 8-अ और अधिकार पत्र की प्रतिलिपि, किसान रजिस्ट्रेशन, विभिन्न खेत उपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड में संशोधन करने के लिए फॉर्म भरने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से वीसीई को विभिन्न योजनाओं की डेटा एंट्री से संबंधित कार्य भी सौंपा जाता है। इसके लिए संबंधित विभाग प्रत्येक कार्य के लिए वीसीई को प्रति यूनिट कमीशन के रूप में देय राशि निर्धारित करता है।

इसके कारण, अलग-अलग कामकाज और अलग-अलग विभागों द्वारा निर्धारित की जाने वाली मेहनताने की राशि अलग-अलग आधार पर तय होने से मेहनताने में समानता नहीं रह पाती।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के ध्यान में जब यह विषय आया, तब उन्होंने हाल ही में ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी की गांधीनगर में आयोजित 12वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीसीई के मेहनताने में समानता के लिए तत्काल निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री के इन दिशा-निर्देशों के चलते पंचायत विभाग ने परिपत्र जारी कर राज्य सरकार के विभागों को सूचित किया है कि अब किसी भी कार्य के लिए वीसीई को प्रति यूनिट न्यूनतम 20 रुपए का मेहनताना देना होगा।

इतना ही नहीं, संबंधित विभागों को वीसीई को कामकाज सौंपने से पहले पंचायत विभाग तथा ई-ग्राम विश्वग्राम सोसाइटी को जानकारी भी देनी होगी।

महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने वडोदरा गोधरा–आणंद रेल खंड का किया संरक्षा निरीक्षण

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने 12 दिसम्बर 2025 को वडोदरा मंडल के वडोदरा – गोधरा – आणंद रेल खंड एवं प्रतापनगर कारखाने का वार्षिक संरक्षा निरीक्षण किया। अपने संरक्षा निरीक्षण में उन्होंने वडोदरा – गोधरा – आणंद रेलखंड में संरक्षा एवं सुरक्षा मानकों, ढांचागत विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं, कर्मचारियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं तथा अन्य प्रगति कार्यों का विस्तृत मूल्यांकन किया। आणंद स्टेशन पर महाप्रबंधक ने आणंद के माननीय विधायक श्री योगेश पटेल ज़ी एवं डाकोर स्टेशन पर थासरा के माननीय विधायक श्री योगेंद्र सिंह परमार ज़ी से मुलाकात की एवं उन्हें मंडल के विकास कार्यों एवं यात्री सुविधाओं की जानकारी दी। महाप्रबंधक के साथ विभिन्न विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्ष, वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके , अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

अपने वार्षिक संरक्षा निरीक्षण के दौरान श्री गुप्ता ने रोड अंडर ब्रिज, महत्त्वपूर्ण बड़े एवं छोटे पुलों, सेक्शनल स्पीड ट्रायल, पॉइंट एवं क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग सहित विभिन्न संरक्षा तत्वों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने वडोदरा, गोधरा, डेरोल एवं डाकोर स्टेशनों पर यात्री प्रतीक्षालय, टिकट बुकिंग सुविधा, शुद्ध पेय जल, पैदल ऊपरी पुल आदि उपलब्ध यात्री सुविधाओं का भी विस्तृत जायजा लिया।

छायापुरी यार्ड में महाप्रबंधक श्री गुप्ता ने पॉइंट एवं क्रासिंग तथा इंजीनियरिंग, ट्रैक्शन, सिग्नलिंग एवं टेलीकम्यूनिकेशन गैंग का निरीक्षण किया और रेल कर्मियों से संरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने छायापुरी – डेरोल खंड के बीच स्पीड ट्रायल का निरीक्षण भी किया।

गोधरा में श्री गुप्ता ने रेलवे स्टेशन के अलावा रेलवे कॉलोनी, गार्ड एवं ड्राइवरों के रनिंग रूम, RPF बैरक का निरीक्षण किया। उन्होंने गोधरा में रेलवे कम्युनिटी हाल का उद्घाटन भी किया।गोधरा - आणंद खंड पर उन्होंने महत्त्वपूर्ण बड़े एवं छोटे पुलों तथा कर्व के साथ - साथ डेरोल - खरसलिया एवं उमरेठ - आणंद खंड पर लेवल क्रासिंग गेट का निरीक्षण किया। श्री गुप्ता ने अपने दौरे के दौरान डेरोल एवं गोधरा में विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया एवं मंडल के उपलब्धिओं एवं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वडोदरा मंडल द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। डेरोल, गोधरा और डाकोर में श्री गुप्ता ने रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया और रेलकर्मियों को गोधरा एवं डाकोर रेलवे कॉलोनी में उनके नए आवास की चाबी का वितरण भी किया।

महाप्रबंधक ने यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संबंधित अधिकारियों को ट्रैक, समपार फाटकों तथा अन्य संरक्षा मानकों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए, ताकि ट्रेन सेवाएँ अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और समयानुसार संचालित की जा सकें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में गुजरात मीडिया क्लब द्वारा आयोजित ‘भारतकूल अध्याय-2’ कार्यक्रम का प्रारंभ कराया

हर आलोचना के पीछे का भाव सकारात्मक तथा लोक कल्याण का होना चाहिए : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलकर विकसित भारत का सपना साकार करेंगे
- विकसित भारत @2047 के संकल्प में गुजरात लीड लेगा
- सनातन मूल्यों के संरक्षण के साथ युवा शक्ति समय के साथ कदम मिलाए

गुजरात के विकास में ‘भाव, राग एवं ताल’ महत्वपूर्ण : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में आयोजित ‘भारतकूल अध्याय-2’ के शुभारंभ अवसर पर मीडिया के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के विकास में मीडिया की भूमिका सहायक की है। सरकार हमेशा नागरिकों की सुख-सुविधा के लिए प्रयत्नशील है, ऐसे में नीतियों में सुधार और लोक कल्याण के लिए उचित आलोचना आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे का भाव सकारात्मक होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में वर्ष-2025 भारत के गौरव को उजागर करने वाला वर्ष बन रहा है। इस वर्ष हम भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती, सरदार साहब की 150 वीं जयंती तथा हमारे राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एकता नगर में गत महीने आयोजित ‘राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस’ तथा भव्य ‘भारत पर्व’ जैसे कार्यक्रमों में अनेकता में एकता का भाव दर्शाती सांस्कृतिक झलक लोगों को देखने को मिली तथा भारतीय परंपरा पुनर्जीवित हुई।

मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति का महत्व समझाते हुए कहा कि विश्व में भारत की पहचान उसकी प्राचीन तथा परम सत्य तक ले जाने वाली संस्कृति के कारण ही है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने पश्चिम के लोगों को भारतीय संस्कृति की केवल एक छोटी-सी झलक ही दिखाई थी, जिससे वे अभिभूत हो गए थे। जो

लोग इसमें गहराई से उतरे, उन्होंने अपना जीवन इस संस्कृति को समर्पित कर दिया। इसलिए यह भी अत्यंत आवश्यक है कि नई पीढ़ी को हमारी सनातन सभ्यता के मूल मूल्यों से अवगत कराया जाए।

श्री पटेल ने ‘भारतकूल’ के इस दूसरे अध्याय के आयोजन के लिए गुजरात मीडिया क्लब और गुजरात यूनिवर्सिटी को बधाई देते हुए, युवा शक्ति को उनके सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को एक उपयुक्त मंच बताया।

उन्होंने बलपूर्वक कहा कि देश को आगे ले जाने और प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो ‘विकसित भारत @2047’ का सपना अवश्य साकार होगा और उसमें गुजरात अग्रसर होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने युवा शक्ति से समय के साथ कदम मिलाते हुए स्वदेशी, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण तथा गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे संकल्पों के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ने का अनुरोध किया।

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने गुजरात के विकास में ‘भाव, राग एवं ताल’ को महत्वपूर्ण बताते हुए ‘भारतकूल’ के कार्यक्रमों में ‘भाव, राग और ताल’ जैसे अद्भुत विषयों का चुनाव करने के लिए आयोजकों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह से गुजरात के विकास की छलांग की शुरुआत की, उसके पीछे राज्य के विकास का भाव मुख्य था। प्रधानमंत्री के मतानुसार अपने राज्य के लिए कुछ अच्छा हो तो खुशी होनी चाहिए और कुछ बुरा हो तो दुख होना चाहिए; यही भावना विकास के लिए अनिवार्य है। उप मुख्यमंत्री ने भाव, राग और ताल; इन तीनों विषयों पर युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने के प्रयासों की सराहना की।

उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में, सरकार में संस्कृति, विरासत, राग और ताल के क्षेत्र में किए गए अद्भुत कार्यों को उल्लेखनीय बताया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वडनगर में देश का सबसे बड़ा म्यूजिक स्टूडियो बनने जा रहा है और वडोदरा में भी इसी प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

श्री संघवी ने कहा कि पिछले 30 वर्षों में संस्कृति संवर्धन सहित क्षेत्रों में जितना काम हुआ है, वह नरेन्द्र मोदी के शासन की शुरुआत से आज तक निरंतर जारी है। उन्होंने रिसर्च डॉक्यूमेंट और चर्चा से निकले सुझावों को सरकार को सौंपने का अनुरोध किया, ताकि ये विषय मात्र कार्यक्रमों तक सीमित न रहें और उन्हें सरकार के कार्यों में जोड़ा जा सके।

अहमदाबाद मंडल की टाइम टेबल पार्सल सेवा: छोटे व्यवसायों के लिए तेज़, सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन सेवा

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा टाइम टेबल पार्सल सेवा (ट्रेन संख्या 00907) का संचालन 21 सितंबर 2025 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। यह साप्ताहिक टाइम-टेबल्ड पार्सल ट्रेन प्रत्येक रविवार को कांकरिया (अहमदाबाद) से प्रस्थान कर संकरैल (कोलकाता) तक 2074 किमी की दूरी मात्र 54 घंटे 45 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन का मार्ग में आणंद, उधना, टाटानगर और खड़गपुर जैसे प्रमुख व्यावसायिक स्टेशनों पर निर्धारित ठहराव उपलब्ध हैं, जिससे देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच तेज़ और विश्वसनीय माल ढुलाई सुनिश्चित होती है। इस ट्रेन में 20 पार्सल वेन (VP) है जिसकी प्रति वेन क्षमता 23 टन है। सिंगल वेन (23 टन) की बुकिंग भी की जा सकती है। इस टाइम टेबल पार्सल सेवा की शुरुआत के बाद से अहमदाबाद मंडल लगातार लोडिंग में प्रमुख योगदान दे रहा है। 20 पार्सल वेन के रेक में औसतन 60–70% पार्सल स्पेस का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। नवंबर 2025 में टाइम टेबल पार्सल सेवा की कुल पाँच ट्रिप संचालित हुईं, जिनसे 0.79 करोड़ का पार्सल राजस्व प्राप्त हुआ। छोटे और मध्यम व्यवसायों की बढ़ती लॉजिस्टिक मांग को ध्यान में रखते हुए यह शुरू की गई है।

इस सेवा ने अब तक 12 सफल यात्राएँ पूरी की हैं, जिनमें 1,78,153 पैकेजों कुशल हेंडलिंग किया गया तथा लगभग 3000 टन माल का परिवहन कर कुल 1.66 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया। लगातार 60% से अधिक लोडिंग उपलब्ध कराना इस बात का प्रमाण है कि यह सेवा बाज़ार की ज़रूरतों को पूर्ण रूप से पूरा कर रही है।

यह तेज़, किफायती और समयबद्ध सेवा छोटे व्यवसायों को निम्न प्रमुख लाभ प्रदान कर रही है —

- तेज़ डिलीवरीः टाइम-टेबल्ड सेवा होने के कारण उत्पाद पूर्वी भारत के बाज़ारों तक निश्चित समय पर पहुँच रहे हैं।
- कम लागत में माल ढुलाईः सड़क परिवहन की तुलना में अधिक सुरक्षित और किफायती विकल्प उपलब्ध हो रहा है।
- व्यापक बाज़ार पहुँचः आणंद, उधना, टाटानगर और खड़गपुर जैसे प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों से सीधा संपर्क छोटे व्यापारियों को नए ग्राहक और नए बाज़ार उपलब्ध करा रहा है।
- त्वरित समाधान और सुगम प्रक्रियाः अहमदाबाद मंडल द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए आसान बुकिंग, तेज़ प्रतिक्रिया और सुव्यवस्थित पार्सल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है।

अहमदाबाद मंडल की यह पहल छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप्स, ई-कॉमर्स विक्रेताओं और स्थानीय उद्योगों के लिए एक प्रभावी, तेज़ और भरोसेमंद परिवहन सुविधा के रूप में उभर रही है। मंडल आगे भी समय-संवेदी लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देते हुए व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे का बोरीवली और गोरेगांव स्टेशनों,के बीच रविवार, 14 दिसम्बर, 2025 को जम्बो ब्लॉक

रेल पथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा बोरीवली और गोरेगांव स्टेशनों के बीच रविवार, 14 दिसम्बर, 2025 को 10.00 बजे से 15.00 बजे तक अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर पांच घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान गोरेगांव और बोरीवली के बीच अप एवं डाउन स्लो लाइन की सभी ट्रेनें फास्ट लाइनों पर चलाई जाएंगी। ब्लॉक के कारण कुछ अप एवं डाउन उपनगरीय ट्रेनें निरस्त रहेंगी तथा अंधेरी और बोरीवली की कुछ ट्रेनें गोरेगांव स्टेशन तक हार्बर लाइन पर चलाई जाएंगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, 2, 3 और 4 से कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी।

फियो ने प्रधानमंत्री के जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के तीन देशों के दौरे का स्वागत किया; इसे व्यापार और आर्थिक साझीदारी को गहरा करने का एक बड़ा अवसर बताया

(जीएनएस)। नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 2025: फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (फियो) प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 15-18 दिसंबर, 2025 तक होने वाले तीन देशों के दौरे की घोषणा का दिल से स्वागत करता है। यह दौरा भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अहम समय पर हो रहा है और पश्चिम एशिया और अफ्रीका में भारत की आर्थिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए बड़ा अवसर प्रदान करता है।

इस घटनाक्रम पर चर्चा करते हुए, फियो के अध्यक्ष, श्री एस सी रल्हन ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में विशेष साझेदारों के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के भारत की प्रतिबद्धता का एक मजबूत संकेत देता है। ऐसे समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव हो रहे हैं, इन साझेदारी को गहरा करने से भारतीय निर्यातकों को नए बाजारों तक पहुंचने, व्यापार मार्गों में विविधता लाने और लंबे समय के व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देने में बहुत मदद मिलेगी।”

महामहिम किंग अब्दुल्ला II इब्न अल हुसैन के आमंत्रण पर 15-16 दिसंबर, 2025 को प्रधानमंत्री का जॉर्डन दौरा राजनयिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ के साथ हो रहा है, जो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और बढ़ते रिश्तों को दिखाता है। उम्मीद है कि बातचीत में द्वीपक्षीय सहयोग के पूरे कार्यक्षेत्र के साथ-साथ क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी बात होगी। श्री रल्हन ने कहा कि जॉर्डन वेस्ट एशिया और बड़े मिडिल ईस्ट रीजन के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे है। अप्रैल-अगस्त, 2025-26 के दौरान जॉर्डन के साथ भारत का कुल द्वीपक्षीय व्यापार 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें सिर्फ़ पांच महीनों में लगभग 461 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ। और इसलिए, जॉर्डन के साथ बेहतर आर्थिक बातचीत से फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, आईटी सर्विसेज़ और फ़ूड और एग्री-प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टरों में भारतीय निर्यातकों के लिए मौके और बढ़ेंगे, जिससे 2030 तक निर्यात बढ़कर 5 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है।

16-17 दिसंबर, 2025 को अपने दौरे के दूसरे हिस्से में, प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. अबी अहमद अली के बुलावे पर इथियोपिया जाएंगे। यह दौरा प्रधानमंत्री का इथियोपिया का पहला दौरा है, जो तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अफ्रीका में भारत के सबसे ज़रूरी साझीदारों में से एक है। फियो प्रमुख ने कहा कि इथियोपिया अफ्रीकी क्षेत्र का एक अहम सदस्य है और भारत के साउथ-साउथ कोऑपरेशन में एक ज़रूरी साझीदार है। यह दौरा व्यापार, निवेश और विकास साझीदारी को गहरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। भारतीय निर्यातक, खासकर ऑटोमोबाइल, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और एजुकेशन सर्विसेज़ में, इथियोपिया के बढ़ते मार्केट में बहुत ज़्यादा संभावना देखते हैं, जहां दोनों देशों के बीच द्वीपक्षीय व्यापार 550 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

प्रधानमंत्री अपने दौरे के आखिरी हिस्से में, महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक के आमंत्रण पर, दूसरी बार 17-18 दिसंबर, 2025 को ओमान जाएँगे। यह दौरा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ है। चूंकि भारत और ओमान एक लंबे समय से चली आ रही और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं, जिसे मज़बूत व्यापार संबंधों,ऊर्जा सहयोग और कल्चरल लिंकेज का सपोर्ट है। श्री रल्हन ने ज़ोर देकर कहा कि ओमान हमेशा से गल्फ में भारत के सबसे भरोसेमंद आर्थिक साझेदारों में से एक रहा है। यह दौरा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, फ़ूड सिक्योरिटी और एमएसएमई सहयोग में नए रास्ते तलाशने का एक शानदार अवसर देता है। ओमान के साथ द्वीपक्षीय संरचना को मज़बूत करने से भारत के निर्यात सेक्टर पर सीधा सकारात्मक असर पड़ेगा, जो 4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का निर्यात है। हालांकि, चूंकि हम एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के आखिरी चरण में हैं। ओमान के साथ हुए इस समझौते से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को दोगुना करने में बहुत ज़रूरी बढ़ावा मिलेगा।

फियो का मानना है कि प्रधानमंत्री का तीन देशों का दौरा भारत की व्यापार कूटनीति को काफ़ी मज़बूत करेगा और बहुत ज़्यादा रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। श्री रल्हन ने भरोसा जताया कि फियो इस ज़रूरी दौरे के नतीजों का इंतज़ार कर रहा है और इन राजनयिक बातचीत को भारतीय निर्यातक समुदाय के लिए ठोस व्यापार और निवेश के मौकों में बदलने के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा और उनके साथ जुड़ेगा।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की सफलता के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के आयोजन का अभिनव दृष्टिकोण

- कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र की रीजनल कॉन्फ्रेंस 10 से 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में आयोजित होगी
- वीजीआरसी के प्रमोशन के लिए दिल्ली में संवाद-वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित
- रशिया, कनाडा और सिंगापुर सहित 20 से अधिक देशों के मिशन और दूतावास के प्रतिनिधी सहभागी हुए
- फिशरीज, पोर्ट, धोलेरा एसआईआर और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर अर्थपूर्ण संवाद का प्लेटफॉर्म

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में 2003 से शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से गुजरात वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर अग्रणी बना है। इतना ही नहीं, गुजरात ने दुनिया भर के उद्योगों-निवेशकों के लिए ‘गेट-वे टू द फ्यूचर’ की विशेष पहचान स्थापित की है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मिली इस सफलता के बाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य विशेषताओं, क्षमताओं और आर्थिक विकास की संभावनाओं को उजागर करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के आयोजन का अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

संतुलित क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास के लिए मार्गदर्शक इस वीजीआरसी के राज्य में चार संस्करण आयोजित करने की योजना के अंतर्गत आगामी 10 से 12 जनवरी, 2026 के दौरान राजकोट में सौराष्ट्र–कच्छ क्षेत्र की वीजीआरसी का आयोजन किया जाएगा।

राज्य सरकार ने इस संदर्भ में शुक्रवार, 12 दिसंबर को नई दिल्ली में एक चर्चा-संवाद सत्र का आयोजन किया। इस चर्चा-संवाद

सत्र में, वीजीआरसी में देश और दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उनके समक्ष वीजीआरसी की विशेषताओं की प्रस्तुति के साथ ही विकास संभावनाओं वाले सेक्टरों को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

इस संवाद सत्र में ‘क्षेत्रीय आकांक्षाएं, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं’ थीम के अनुरूप और समावेशी, नवोन्मेषी एवं सतत-टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए गुजरात की विशेषताएं प्रस्तुत की गईं। विशेषकर, फिशरीज, पोर्ट्स, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर) और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर सार्थक संवाद और बीटूबी (बिजनेस-टू-बिजनेस) की संभावनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा-परामर्श हुआ। साथ ही, वीजीआरसी में साझेदार देश बनने के फायदे, नेटवर्किंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे विषयों पर भी वार्तालाप किया गया।

उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप ने चर्चा सत्र में मेहसाणा में आयोजित उत्तर गुजरात क्षेत्र की पहली वीजीआरसी को मिली सफलता और 3.24 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की जानकारी दी।

इस संवाद में रशिया, इजरायल, सिंगापुर, यूएई, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, कनाडा, श्रीलंका, ओमान, आइसलैंड, गुयाना, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, कतर, तंजानिया, युगांडा और उज्बेकिस्तान सहित 20 से अधिक देशों के विदेशी मिशन और दूतावासों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव, केंद्रीय मत्स्य पालन संयुक्त सचिव और इन्वेस्ट इंडिया की राज्य सुविधा टीम तथा गुजरात सरकार के उद्योग एवं खान विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती ममता वर्मा, आर्थिक मामलों की सचिव श्रीमती आरती कंवर, सचिव श्री संदीप कुमार, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप, पर्यटन सचिव डॉ. राजेन्द्र कुमार, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के सीईओ श्री राजकुमार बेनीवाल, रेजिडेंट कमिश्नर सह मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और धोलेरा एसआईआर के सीईओ श्री कुलदीप आर्य मौजूद रहे।

सोना-चांदी के वायदा में तेजी जारीः दोनों कीमती धातुओं के वायदाओं में ऑल टाइम हाई भाव दर्ज हुए

क्रूड ऑयल वायदा में 36 रुपये की वृद्धिः कमोडिटी वायदाओं में 54159.48 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 204265.12 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 45147.02 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 32936 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 258438.51 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 54159.48 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 204265.12 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 32936 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3278.41 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 45147.02 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 132442 रुपये के भाव पर खूलकर, 134966 रुपये के ऑल टाइम हाई और 132275 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 132469 रुपये के पिछले बंद के सामने 2432 रुपये या 1.84 फीसदी की मजबूती के साथ 134901 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 2021 रुपये या 1.91 फीसदी बढ़कर 107727 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 245 रुपये या 1.85 फीसदी बढ़कर 13484 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। सोना-मिनी जनवरी वायदा 130905 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 133072 रुपये और नीचे में 130552 रुपये पर पहुंचकर, 2115 रुपये या 1.62 फीसदी बढ़कर 133020 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम 131334 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 133388 रुपये और नीचे में 130901 रुपये पर पहुंचकर, 131137 रुपये के पिछले बंद के सामने 2163 रुपये या 1.65 फीसदी बढ़कर 133300 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 196958 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 201388 रुपये के ऑल टाइम हाई और नीचे में 196957 रुपये पर पहुंचकर, 198942 रुपये के पिछले बंद के सामने 1589 रुपये या 0.8 फीसदी बढ़कर 200531 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1783 रुपये या 0.9 फीसदी की तेजी के संग 200993 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1785 रुपये या 0.9 फीसदी की मजबूती के साथ 201008 रुपये प्रति किलो बोला गया। मेटल वर्ग में 5113.39 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 7.55 रुपये या 0.68 फीसदी बढ़कर 1119.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 2.2 रुपये या 0.69 फीसदी की तेजी के संग 322.3 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 10 पैसे या 0.04 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 280.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 25 पैसे या 0.14 फीसदी बढ़कर 182.15 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3745.73 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा 5230 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5260 रुपये और नीचे में 5200 रुपये पर पहुंचकर, 36 रुपये या 0.7 फीसदी बढ़कर 5215 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी दिसंबर वायदा 36 रुपये या 0.69 फीसदी की तेजी के संग 5216 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 380.9 रुपये के भाव पर खूलकर, 386.2 रुपये के दिन के उच्च और 370.7 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 381.1 रुपये के पिछले बंद के सामने 4.4 रुपये या 1.15 फीसदी की बढ़त के साथ 385.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 4.1 रुपये या 1.08 फीसदी बढ़कर 385.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 909.5 रुपये पर खूलकर, 3.1 रुपये या 0.33 फीसदी गिरकर 925.1 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 24432.28 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 20714.74 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4332.68 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 248.12 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 19.38 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 513.22 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 903.18 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2829.68 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 15256 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 71979 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 18847 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 298492 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 32784 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 17400 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 41713 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 118375 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 18628 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 40170 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 32632 पॉइंट पर खूलकर, 32975 के उच्च और 32400 के नीचले स्तर को छूकर, 373 पॉइंट बढ़कर 32936 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल दिसंबर 5300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 70 पैसे के सुधार के साथ 32 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 380 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.45 रुपये की बढ़त के साथ 21.7 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 136000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 874 रुपये की बढ़त के साथ 2058.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 198000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1077 रुपये की बढ़त के साथ 7908 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.46 रुपये की बढ़त के साथ 19.5 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 315 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3.48 रुपये की बढ़त के साथ 10.84 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल दिसंबर 5200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 22.1 रुपये की गिरावट के साथ 61.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 380 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5 पैसे की नरमी के साथ 17 रुपये हुआ।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं अजमेर के बीच,चलाएगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अजमेर में उर्स फेस्टिवल के लिए यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को समायोजित करने के लिए बांद्रा टर्मिनस एवं अजमेर स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09027/09028 बांद्रा टर्मिनस – अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल [04 फेरे]

ट्रेन संख्या 09027 बांद्रा टर्मिनस – अजमेर स्पेशल सोमवार और गुरुवार, 22 एवं 25 दिसंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 12:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:20 बजे अजमेर पहुंचेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09028 अजमेर – बांद्रा टर्मिनस स्पेशल मंगलवार और शुक्रवार, 23 एवं 26 दिसंबर, 2025 को अजमेर से 10:25 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, दहानू रोड, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर और नसीराबाद स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09027 की बुकिंग 14 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे चलायेगी साबरमती और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच क्रिसमस स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा क्रिसमस और नववर्ष के दौरान यात्रियों की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए साबरमती और दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

ट्रेन संख्या 04061/4062 साबरमती-दिल्ली सराय रोहिल्ला-साबरमती स्पेशल (8 फेरे)

ट्रेन संख्या 04061 साबरमती-दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल 22, 25, 28 और 31 दिसंबर 2025 को साबरमती से प्रातः 05.15 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन रात्री 23.30 बजे दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। इसी तरह से ट्रेन संख्या 04062 दिल्ली सराय रोहिल्ला-साबरमती स्पेशल 21, 24, 27 और 30 दिसंबर 2025 को दिल्ली सराय रोहिल्ला से 08.10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 00.30 बजे

साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जं., ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर-जयपुर, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुडगाँव एवं दिल्ली केंट स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन एसी I-टियर एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। ट्रेन संख्या 04061 की बुकिंग 14 दिसंबर 2025 सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।